



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

CH
2/8/85

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 450]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 20, 1984/कार्तिक 29, 1906

No. 450]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 20, 1984/KARTIKA 29, 1906

हम भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(विदेशी कर प्रभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1984

आय-कर

सां० का० नि० 786 (अ) :—भारत गणराज्य की सरकार और फिनलैंड गणराज्य की सरकार के बीच आय पर और पूँजी अभिलक्षण पर दोहरे कराधान का परिचर्जन करने के लिए हमने उपाबद्ध कन्वेंशन दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा संविधानिक अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के बारे में एक दूसरे का अधिसूचना कर देने पर, जो उक्त कन्वेंशन के अनुच्छेद 29 के पैरा 1 द्वारा अपेक्षित है, प्रवृत्त हो गया है:

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90, कंपनी (लाभ) अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 24 क और धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 44 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त कन्वेंशन के सभी उपबंधों का भारत संघ में प्रभावी किया जाएगा।

उपाबंध

भारत गणराज्य

और

फिनलैंड गणराज्य

के बीच

आय तथा पूँजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के पारहार के लिए अति-समय

भारत गणराज्य सरकार और फिनलैण्ड गणराज्य सरकार, आय पर तथा पूँजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार के लिए एक नया अभिसमय करने की इच्छा से,

नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई हैं :

अनुच्छेद 1

व्यक्तिगत क्षेत्र

यह अभिसमय उन व्यक्तियों पर लागू होगा, जो किसी एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के निवासी हैं।

अनुच्छेद 2

अभिसमय के अंतर्गत आने वाले कर

1. वर्तमान अभिसमय जिन करों पर लागू होगा, वे हैं :—

(क) फिनलैण्ड में :

- (1) राज्य आय तथा पूँजी कर ;
 - (2) साम्प्रदायिक कर ;
 - (3) गिरजा घर कर ;
 - (4) नाविक कर, तथा
 - (5) अनिवासी की आय से स्रोत पर रोका गया कर ;
- (जिन्हें इसके बाद “फिनिश कर” कहा जाएगा)

(ख) भारत में :

- (1) आयकर जिसमें उस पर लगने वाला कोई भी अधिनियम शामिल है ;
 - (2) अधिकार ; तथा
 - (3) धनकर ;
- (जिन्हें इसके बाद “भारतीय कर” कहा जाएगा)

2. यह अभिसमय वर्तमान करों अथवा उनकी जगह लगाये जाने वाले करों के अतिरिक्त किसी भी समरूप अथवा भारत : वैसे ही करों पर भी लागू होगा जो अभिसमय पर हस्ताक्षर किये जाने की तारीख के बाद लगाये जायेंगे। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी अपने-अपने कराधान कानूनों में किये गये महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में एक दूसरे को सूचित करेंगे।

अनुच्छेद 3

सामान्य परिभाषाएं

1. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो ;

- (क) “व्यक्ति” पद में कोई व्यक्ति, कंपनी और व्यक्तियों का कोई अन्य निकास शामिल है ;
- (ख) “कंपनी” पद से कोई ऐसा निर्गमित निकाय अथवा कोई भी सत्ता अभिप्रेत है जो कर प्रयोजनों के लिए निर्गमित निकाय के रूप में मानी जाती है ;

(ग) “एक संविदाकारी राज्य का उद्यम” तथा “दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम” पद से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित उद्यम अभिप्रेत होगा ;

(घ) “राष्ट्रिक” पद से, किसी संविदाकारी राज्य की राष्ट्रिकता वाला कोई व्यक्ति, और कोई भी कानूनी व्यक्ति, भागीदारिता तथा संघ, जो एक संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानून से इस प्रकार अपनी हैसियत प्राप्त करता हो, अभिप्रेत है ;

(ङ) “अन्तर्राष्ट्रीय यातायात” पद से किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा संचालित जलयान अथवा वायुयान परिवहन अभिप्रेत है, इसलिए उस स्थिति के जब यात्रा मात्र दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्थानों के बीच की जाती हो ;

(च) “सक्षम प्राधिकारी” पद से अभिप्रेत है ;

- (1) फिनलैण्ड में, वित्त मंत्रालय अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि ;
- (2) भारत में, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)।

2. जहां तक संविदाकारी राज्य द्वारा इस अभिसमय को लागू करने का संबंध है, किसी भी पद का, जो इसमें परिभाषित नहीं हो, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, वही अर्थ होगा जो उस राज्य के उन करों से संबंधित कानूनों के अंतर्गत होता है जिन पर वह अभिसमय लागू होता है।

अनुच्छेद 4

आर्थिक अधिवास

(1) इस अभिसमय के प्रयोजनों के लिए, “संविदाकारी राज्य का निवासी” पद से अभिप्रेत होगा कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर, उस राज्य के कानून के अंतर्गत उसके अधिवास, निवास, प्रबंध स्थान अथवा इस प्रकार की किसी अन्य कसौटी के कारण वहां कर लगाया जा सकता है।

(2) जहां पैराग्राफ (1) के उपबंधों के कारण कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहां उसका दर्जा नीचे लिखे नियमों के अनुसार तय किया जाएगा :

(क) वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जायेगा जहां उसे एक स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो। यदि उसे दोनों संविदाकारी राज्यों में स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर हैं (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र) ;

(ख) यदि उस संविदाकारी राज्य का, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित हैं, निश्चय नहीं किया जा

सकता हो, अथवा यदि उसको किसी भी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी निवास उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें वह आश्रय प्राप्त करता हो ;

(ग) यदि वह आश्रय प्राप्त दोनों ही राज्यों में रहता हो अथवा उनमें किसी भी राज्य में आश्रय प्राप्त नहीं करता हो तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसका वह राष्ट्रिक है ;

(घ) यदि वह दोनों संविदाकारी राज्यों का राष्ट्रिक हो अथवा उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक न हो तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी परस्पर सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे।

3. जहाँ पैराग्राफ (1) के उपबंधों के कारण से, व्यक्ति से अलग कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसके प्रवासी प्रबंध का स्थान स्थित है।

अनुच्छेद 5

स्थायी स्थापन

(1) इन अनुसूचियों के प्रयोजनों के लिए, "स्थायी स्थापन" पद का अर्थ है, कारोबार का वह निश्चित स्थान जहाँ किसी उद्यम का कारोबार पूर्णतः अथवा अंशतः किया जाता है।

(2) "स्थायी स्थापन" पद में विशेष तथा निम्नलिखित शामिल होंगे :

- (क) प्रबंध का कोई स्थान ;
- (ख) कोई शाखा ;
- (ग) कोई कार्यालय ;
- (घ) कोई कारखाना ;
- (ङ) कोई कार्यशाला ;
- (च) कोई खान खदान अथवा ऐसा कोई अन्य स्थान जहाँ से प्राकृतिक संसाधन निकाले जाते हैं ;
- (छ) कोई मालगोदाम ; और
- (ज) कोई परिसर जहाँ से विक्रय कार्य किया जाता हो अथवा जहाँ विक्रय आदेश प्राप्त किये जाते हों अथवा मंगाए जाते हों।

3. "स्थायी स्थापन" पद में निम्नलिखित भी शामिल हैं :

- (क) कोई भवन स्थल कोई निर्माण संयोजन अथवा संस्थापना परियोजना अथवा उसके संबंध में पर्यवेक्षी गतिविधियाँ परन्तु वहीं जहाँ इस प्रकार का स्थल, परियोजना अथवा गतिविधियाँ छः महीने से अधिक अवधि तक जारी रहती हों ;
- (ख) कोई भवन स्थल कोई निर्माण संयोजन अथवा संस्थापना परियोजना अथवा पर्यवेक्षी गतिविधियाँ जो मशीनरी अथवा उपकरणों के विक्रय से संबंध

रखती हों जहाँ इस प्रकार का स्थल परियोजना अथवा गतिविधि छः महीने से अधिक अवधि तक जारी न रहे और उस परियोजना अथवा पर्यवेक्षी गतिविधि के लिए देश प्रभार मशीनरी और उपकरण के विक्री मूल्य के दम प्रतिशत से अधिक हों।

4. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होने हुए भी "स्थायी स्थापन" पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जाएगा :

- (क) किसी उद्यम के माल अथवा तिजारती सामान के केवल भंडारण अथवा उसके प्रदर्शन के उद्देश्य से किन्हीं सुविधाओं का प्रयोग
- (ख) केवल भंडारण अथवा प्रदर्शन के उद्देश्य से उद्यम के माल अथवा तिजारती सामान का स्टॉक रखना ;
- (ग) किसी उद्यम द्वारा केवल संसाधित किये जाने के उद्देश्य से ही उद्यम के माल अथवा तिजारती माल का स्टॉक रखना ;
- (घ) किसी उद्यम के लिए माल अथवा तिजारती माल खरीदने अथवा सूचना एकत्र करने के उद्देश्य मात्र के लिए ही व्यवसाय का कोई निश्चित स्थान रखना ;
- (ङ) केवल विज्ञापन के लिए सूचना देने के लिए अथवा वैज्ञानिक अनुसंधान के उद्देश्य से ही जो संबंधित उद्यम के व्यापार में पूर्णतः प्रासंगिक अथवा सहायक स्वरूप की गतिविधियाँ ही होती हैं व्यवसाय का कोई निश्चित स्थान रखना।

5. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंधों के होने हुए भी, जहाँ किसी स्वतंत्र हैसियत के अंतर्गत से भिन्न कोई व्यक्ति जिस पर पैराग्राफ 7 लागू होता हो—किसी संविदाकारी राज्य में अन्य संविदाकारी राज्य के उद्यम की ओर से कार्य कर रहा हो वहाँ उन कार्यों के संबंध में जिन्हें वह व्यक्ति उद्यम के लिए अपने जिम्मे लेता है प्राथमिक संविदाकारी राज्य में उस उद्यम का उस स्थिति में स्थायी स्थापन माना जाएगा यदि इस प्रकार के व्यक्ति को :

- (क) उस राज्य में उद्यम के नाम पर संबिदाएं संपन्न करने का प्राधिकार प्राप्त हो और वह प्रायः उस अधिकार का प्रयोग करता हो और जब तक ऐसे व्यक्ति की गतिविधियाँ पैराग्राफ 4 में उल्लिखित गतिविधियों तक सीमित न हों यदि उन्हें कारोबार के किसी निश्चित स्थान के माध्यम से किया जाए तो कारोबार का यह नियत स्थान उस पैराग्राफ के उपबंधों के अधीन एक स्थायी स्थापन नहीं होगा ; अथवा

(ख) ऐसा कोई प्राधिकार नहीं है, परन्तु वह प्रयोज्यलिखित संविदाकारी राज्य में आमतीय से माल अथवा तिजारीती नाम का पण्डार रखता है। जिसमें से वह उन उद्यम की आर में माल अथवा तिजारीती माल की नियमित रूप में डिलिवरी करता है।

6. इस अनुच्छेद के पूर्वार्थी उपबंधों के होने हुए भी एक संविदाकारी राज्य के किसी बीना उद्यम का पुनः बाने को छाड़कर, दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थायी स्थापन का होता मान लिया जाएगा यदि वह उस दूसरे राज्य के क्षेत्र में प्रतीयन बल का है अथवा स्वतंत्र हैसियत के किसी अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति के माध्यम से जिस पर पैरा 7 लागू होता है, उस क्षेत्र में स्थित जांखिमों का बीना करता है।

7. किसी उद्यम का किसी संविदाकारी राज्य में केवल इसलिए कोई स्थायी स्थापन होता नहीं माना जाएगा कि वह किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत के किसी अन्य एजेंट के माध्यम से उस राज्य में कारोबार करता है बशर्ते कि वहां उपर्युक्त प्रकार के व्यक्ति इस तरह का कारोबार सामान्यतः करते हैं लेकिन यदि इस प्रकार के एजेंट की कार्य-बाहियां पूर्णतः अथवा लगभग पूर्णतः उस उद्यम विशेष की आर से की जाती हैं तो उसे इन पैराग्राफ के अर्थ के प्रयोजन में स्वतंत्र हैसियत का एजेंट नहीं माना जाएगा।

8. मात्र इस तथा से कि कोई कंपनी जो किसी एक संविदाकारी राज्य की निवासी है किसी ऐसे कंपनी को नियंत्रित करती है अथवा उनसे नियंत्रित होती है जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में अपना कारोबार करती है (किसी स्थायी स्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) इनमें से कोई भी कंपनी खुद किसी दूसरी कंपनी का स्थायी संस्थापन नहीं बन सकती।

अनुच्छेद 6

अचल सम्पत्ति से आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल संपत्ति से (जिसमें कृषि अथवा जंगल में से प्राप्त होने वाली आय भी शामिल है) प्राप्त आय पर कर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में लगाया जाएगा।

2. (क) उप पैरा (ख) तथा (ग) के उपबंधों के अधीन रहते हुए "अचल संपत्ति" पद का अर्थ वही है जो उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अधीन है जहां संबंधित संपत्ति स्थित है।

(ख) "अचल संपत्ति" पद में किसी भी हालत में ये शामिल होंगे अचल संपत्ति के उपसाधन के रूप

में संपत्ति कृषि और वन-संपत्ति में प्रयुक्त पशुधन तथा उनकर ऐसे अधिकार जिन पर भू-संपत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हैं अचल संपत्ति का बाने के अधिकार और खनिज पण्डार खान तथा अन्य प्राकृतिक साधनों के संचालन के लिए अथवा कार्य करों के अधिकार के प्रविफन के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदा-वियां के अधिकार।

(ग) पंजी तथा विमान अचल संपत्ति नहीं माने जाएंगे।

3. पैरा 1 के उपबंध अचल संपत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग किये पर दो से अथवा किसी अन्य प्रकार से प्राप्त आय पर लागू होंगे।

4. जहां किसी कंपनी के द्वारा का स्वामित्व अथवा अन्य नियमित अधिकार, ऐसे क्षेत्रों अथवा नियमित अधिकारों के स्वामी का, कंपनी द्वारा धारित अचल संपत्ति के उपयोग का हकदार बनाते हैं वहां प्रत्यक्ष उपयोग किये पर देने अथवा उपयोग के ऐसे अधिकार के किसी अन्य प्रकार से उपयोग द्वारा प्राप्त आय पर कर उस संविदाकारी राज्य में लगाया जाएगा जिसमें वह संपत्ति स्थित है।

5. पैराग्राफ 1 और 3 के उपबंध किसी उद्यम की संपत्ति से प्राप्त आय पर कर स्वतंत्र व्यक्तियों सेवाओं के निष्पादन में प्रयुक्त संपत्ति से प्राप्त आय पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद 7

कारोबार से लाभ

1. संविदाकारी के किसी उद्यम के लाभ पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी स्थापन के माध्यम से कारोबार न करता हो। यदि कोई उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता है, तो उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है, परन्तु उसके केवल उतने अंश पर ही कर लगेगा जो (क) उस स्थायी स्थापन; (ख) उस दूसरे राज्य में उसी अथवा उसी प्रकार की वस्तुओं अथवा तिजारीती माल की बिक्री जो उस स्थायी स्थापन के माध्यम से की जाती है; अथवा (ग) उस दूसरे राज्य में की जाने वाली कारोबार संबंधी वैसी ही अन्य गतिविधियों अथवा उसी प्रकार की गतिविधियां, जो उस स्थायी स्थापन के माध्यम से की जाती हों, के कारण हुआ माना जा सकता है।

2. पैरा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए यदि किसी संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी स्थापन द्वारा कारोबार करता हो, तो प्रत्येक संविदाकारी राज्य में होने वाले लाभ को उस स्थायी स्थापन का ही लाभ समझा जाएगा, जिसे उसके द्वारा प्राप्त होने की तब अपेक्षा की जाती जब वह उन्हीं या वैसी ही पारस्थितियों में उन्हीं या वैसी ही कार्यों में लगा हुआ कोई निश्चित और निश्च उद्यम होता और उस उद्यम

के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से काराबार करता, जिसका यह एक स्वार्थी स्थापन है।

3. किसी स्थयी स्थापन के लाभों के निर्धारण में उन व्यक्तियों की कटौतियों के रूप में स्वीकार किया जाएगा, जो स्थयी स्थापन के काराबार के प्रयासों के लिए किये गए हों, और उनमें इन प्रकार किए गए कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक कार्य शामिल रहेंगे चाहे वे उस राज्य में किये गए हों जहां स्थयी स्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र, और जिसकी स्वीकृति उस संबन्धी राज्य के अपने अधिकार गणन के उपबंधों के अंतर्गत दी जाती है, जहां स्थयी स्थापन स्थित है। लेकिन स्थयी स्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान-कार्यालय को अथवा उसके अन्य कार्यालयों में से किसी को (वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से निम्न रूप में), पेटेंटों अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले स्वामित्व, फीज अथवा अन्य ऐसी ही प्रदायकों के रूप में, अथवा दी गई विशिष्ट सेवाओं अथवा प्रबंध के लिए कमीशन के रूप में अथवा बौद्धिक उद्यम के मामले का छाड़कर स्थयी स्थापन को उधार दिये गए धन पर ब्याज के रूप में, याद कोई एकमें अथवा की गई हों, तां उनके संबंध में ऐसी किसी वटोती, की स्वीकृति नहीं दी जाएगी इसी प्रकार स्थयी स्थापन के लाभों के निर्धारण में उन लाभों को हितान से नहीं लिया जाएगा, जो स्थयी स्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय का या उसके अन्य कार्यालयों में से किसी को (वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से निम्न रूप में), स्थयी स्थापन द्वारा पेटेंटों अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले में स्वामित्व, फीज अथवा अन्य ऐसी ही अदायगियों के रूप में अथवा की गई विशिष्ट सेवाओं के लिए अथवा प्रबंध के लिए कमीशन के रूप में अथवा बौद्धिक उद्यम के मामले का छाड़कर अन्य मामलों में, उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा उसके किसी अन्य कार्यालयों में से किसी को उधार दिए गए धन पर ब्याज के रूप में उद्यम के प्रधान कार्यालय या अन्य कार्यालयों में से किसी को प्रसारित की गई हों।

4. जहां किसी संबन्धीकारी राज्य में, उद्यम के कुल लाभों के उसके लाभ अंशों के प्रति अनुमजन के आधार पर, किसी स्थयी स्थापन के कारण माने जाने वाले लाभों को निश्चिन्ता करने की प्रथा है, वहां पैराग्राफ 2 की कोई भी बाधना उस संबन्धीकारी राज्य का ऐसी यथ-सिद्ध प्रवृत्ति से, कर लगने वाले लाभों का निश्चिन्ता करने से प्रतिबन्धित नहीं करेगी। तथापि अन्तर्गत गरी प्राप्ति पद्धति ऐसी होगी कि उसका परिणाम इस अनुच्छेद में विहित सिद्धांतों के अनुसार होगा।

5. कोई भी, मात्र इस कारण स्थयी स्थापन का ह्रास नहीं माने जायेगा कि उस स्थयी स्थापन द्वारा उद्यम के लिए माल अथवा पण्य धस्तुएं खरीदी गई है।

6. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनों के लिए, स्थयी स्थापन के कारण माने जाने वाले लाभों का तब तक उद्यम पद्धति से धर्नातुव निर्धारित किया जाएगा जब तक कि उसके विरुद्ध उद्युक्त तथा पर्याप्त कारण नहीं हों।

7. जहां लाभों में अथवा की वे अथवा शामिल हों, जिसका इस अधिनियम के अन्य अनुच्छेदों में प्रत्यक्ष से विवेचन किया गया है, वहां उन अनुच्छेदों के उपबंध से प्रभाव नहीं होंगे।

अनुच्छेद 8

विमान-परिवहन

1. एक संबन्धीकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में विमान परिवहन में प्रयुक्त आय पर केवल उसी राज्य में ही कर लगाया जाएगा।

2. पैराग्राफ 1 इसी तरह विमान परिवहन में लगे उद्यमों द्वारा किसी भी प्रकार के पूर्णों में भाग लेने के संबंध में लागू होगा।

3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए:

(क) अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में वायुयान संचालन से सम्बद्ध निधियों पर ब्याज का ऐसे वायुयान संचालन से होने वाले आय माना जाएगा; और

(ख) "वायुयान संचालन" पद के अंतर्गत वायुयान के मालिकों अथवा पट्टेदारों अथवा अधिकृतियों (चार्टरर्स) द्वारा वायुयान के जरिये किया जाने वाला व्यक्तियों, पशु-धन, माल अथवा डाक का परिवहन, जिसमें अन्य उद्यमों की तरफ से ऐसे परिवहन के लिए टिकटों की बिक्री किराया-आधार पर वायुयान का प्रासंगिक पट्टा तथा इन प्रकार के परिवहन से प्रत्यक्षतः सम्बद्ध अन्य कोई कार्य-कलाप शामिल हैं।

अनुच्छेद 9

जहाजरानी

1. एक संबन्धीकारी राज्य के उद्यम का दूसरे संबन्धीकारी राज्य से, अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में पोत परिवहन से हुई आय पर उस दूसरे संबन्धीकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है लेकिन ऐसी आय पर उस दूसरे संबन्धीकारी राज्य में प्रमरीय कर का ऐसे कर के पचास प्रतिशत के बराबर कम कर दिया जाएगा।

2. पैराग्राफ 1 नववर्ती यातायात के परिणामतः उत्पन्न होने वाले लाभों पर लागू नहीं होता।

अनुच्छेद 10

सहयोगी उद्यम

अर्थात्—

(क) एक संबन्धीकारी राज्य का उद्यम दूसरे संबन्धीकारी राज्य के उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है, अथवा

(ख) वे ही व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम के प्रबंध नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं ;

और दोनों में से किसी भी अवस्था में, दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं, जो वैसी शर्तों से भिन्न हैं, जैसी स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं, वहां ऐसा कोई लाभ जो उन शर्तों के न होने की हालत में उन उद्यमों में से एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, परन्तु उन शर्तों के कारण प्राप्त नहीं हुआ, तो वह लाभ उस उद्यम के लाभों में सम्मिलित किया जा सकेगा और और वे तदनुसार कराधेय हो सकेंगे।

अनुच्छेद 11

लाभांश

1. जो कंपनी एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, उसके द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा किये गये लाभांश उस दूसरे राज्य में कराधेय हो सकते हैं।

2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर भी उस संविदाकारी राज्य में और उसी राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकता है जिसकी वह लाभांश देने वाली कंपनी निवासी है, परन्तु इस प्रकार लगाया गया कर नीचे बतायी गई रकम से अधिक नहीं होगा :

(क) लाभांशों की सकल रकम का 15 प्रतिशत, यदि प्राप्तकर्ता (भागीदारी से भिन्न) कोई ऐसी कंपनी है जिसके पास, लाभांश अदा करने वाली कंपनी की कम से कम 10 प्रतिशत पूंजी हो ;

(ख) अन्य सभी मामलों में लाभांशों की सकल रकम का 25 प्रतिशत। यह पैराग्राफ ऐसे लाभों के संबंध में कंपनी के कारधान को प्रभावित नहीं करेगा जिसमें से लाभांश अदा किये जाते हैं।

3. पैराग्राफ 2 के उप-पैराग्राफ (क) के उपबंध इस अभिसमय पर हस्ताक्षर की तारीख के बाद किये गये निवेशों से उत्पन्न लाभांशों के संबंध में लागू होंगे।

4. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "लाभांशों" शब्द का अभिप्राय है शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से, जो ऋण दावे नहीं हों, प्राप्त आय, जो लाभ में शामिल हों तथा अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त आय जिन पर उसी प्रकार की कराधान व्यवस्था लागू होती है जिस प्रकार उस राज्य के कानूनों द्वारा शेयरों से प्राप्त आय के मामले में लागू होती है जिसमें वितरण करने वाली कंपनी निवासी है।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि लाभांश प्राप्त करने वाला, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में जिसकी, लाभांश अदा करने वाली कंपनी निवासी है, वहां स्थिति एक स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से, व्यापार करता है अथवा वह उस दूसरे राज्य में स्थित एक नियत स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है और जिस धारिता के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है, वहां इस प्रकार के स्थायी प्रतिष्ठान अथवा नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है। ऐसे मामलों में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के, जैसा भी मामला हो, उपबंध लागू होंगे।

6. जहां कोई कंपनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहां वह अन्य राज्य, कंपनी द्वारा अदा किये गये लाभांशों पर किसी प्रकार का कर नहीं लगाएगा जहां तक कि उस अन्य राज्य के निवासी को इस प्रकार के लाभांश अदा नहीं किये जाते अथवा जहां तक कि नियंत्रक कंपनी जिसके संबंध में लाभांश अदा किये जाते हैं, उस अन्य राज्य में स्थित एक स्थायी प्रतिष्ठान अथवा एक निश्चित आधार से प्रभावी रूप से सम्बद्ध नहीं हैं, और न ही कंपनी के अवितरित लाभों पर कंपनी के अवितरित लाभों संबंधी कर लगाया जाएगा, चाहे अदा किये गये उक्त लाभांश अथवा अवितरित लाभ में, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से, उस दूसरे राज्य में उत्पन्न होने वाला लाभ अथवा आय शामिल हो।

अनुच्छेद 12

ब्याज

1. एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न हुए दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा किये गए ब्याज पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में कर लगाया जाएगा बशर्ते कि इस प्रकार प्रभारित कर, ब्याज की सकल रकम के 15 प्रतिशत से अधिक न हो।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, इस अभिसमय के हस्ताक्षर की तारीख के बाद किये गये पूंजी-निवेशों से उत्पन्न संवेय ब्याज के संबंध में लागू होंगे।

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "ब्याज" शब्द से अभिप्रेत है प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधी दावों से प्राप्त आय चाहे वे बंधक द्वारा प्रतिभूत हों अथवा नहीं और चाहे उनको ऋणदाता के लाभों में भागीदारी का अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं, और खासतौर पर सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बंध-पत्रों अथवा ऋण-पत्रों से, जिनमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंध-पत्रों अथवा ऋण-पत्रों के संबंध में प्रदान किये जाने वाले प्रीमियम और पुरस्कार शामिल हैं, से प्राप्त

आय। विलम्बित अदायगी के लिए अर्थदण्ड संबंधी प्रभारों को इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए व्याज नहीं समझा जाएगा।

4. पैराग्राफ 1 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि व्याज प्राप्तकर्ता जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें व्याज उत्पन्न हुआ हो, स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से व्यापार चलाता है, अथवा वह उस दूसरे राज्य में, वहां स्थित एक निश्चित स्थान से, स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है और जिस ऋण-दावे के बारे में व्याज अदा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी प्रतिष्ठान अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है। इस प्रकार के मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

5. व्याज, किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ, माना जाएगा, यदि व्याज अदा करने वाला स्वयं उक्त राज्य कोई राजनीतिक उप-मंडल, कोई सांविधिक निकाय, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो। किन्तु, जहां व्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, संविदाकारी राज्य में एक स्थायी प्रतिष्ठान अथवा निश्चित स्थान है, जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था जिस पर व्याज की अदायगी की गई है, इस प्रकार का व्याज उस स्थायी प्रतिष्ठान अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है, तब वह व्याज उस राज्य में उद्भूत माना जाएगा जिसमें वह स्थायी प्रतिष्ठान अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

6. जहां व्याज अदा करने वाले तथा उसके प्राप्तकर्ता के बीच अथवा उन दोनों के और किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण, अदा की गई व्याज की रकम, उस ऋण-दावे को ध्यान में रखते हुए जिसके लिये व्याज की रकम अदा की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके लिये इस प्रकार के संबंध नहीं होते की स्थिति में अदा करने वाले और प्राप्तकर्ता के बीच सहमति हो गयी होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम वर्णित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदायगी के अतिरिक्त भाग पर, इस अभिसमय के अन्य उपबंधों का सम्यक अनुपालन करते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 13

तकनीकी सेवाओं के लिए रायल्टियां और शुल्क

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को तकनीकी सेवाओं के लिए अदा की गयी रायल्टियों और शुल्कों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. तथापि, तकनीकी सेवाओं के लिए रायल्टियों और शुल्कों पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के

कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसमें वे उद्भूत हुए हों; बशर्ते कि जहां तकनीकी सेवाओं के लिए रायल्टियां अथवा शुल्क अन्य संविदाकारी राज्य के ऐसे निवासी को अदा किए गए हों जो उनका लाभकारी स्वामी हो और यह किसी ऐसे अधिकार अथवा संपत्ति के सिलसिले में दिए गए हों जो पहले दी जा चुकी हो अथवा किसी ऐसी संविदा के अंतर्गत दिए जाएं जो इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद सम्पन्न की गई हो, और इस तरह जो कर लगाया जाएगा वह तकनीकी सेवाओं की रायल्टी और शुल्क की सकल राशि के तीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "रायल्टियों" शब्द से :-

- (क) कोई पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन अथवा माडल, प्लान, गुप्त फार्मूला अथवा प्रक्रिया ;
- (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपस्कर अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित जानकारी ;
- (ग) कोई साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कृतियों, चलचित्रों-फिल्मों तथा रेडियो अथवा दूरदर्शन प्रसारण के लिए फिल्में अथवा टेपों, के प्रति-लिप्याधिकार ;

के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए प्रतिफल के रूप में, जिसमें किराया भी शामिल है, प्राप्त किसी प्रकार की अदायगी अभिप्रेत है किन्तु इसमें खानों अथवा खदानों के कार्यचालन अथवा प्राकृतिक साधनों के निकालने अथवा हटाने के संबंध में अदा की गई रायल्टियां अथवा अन्य रकमों सम्मिलित नहीं हैं।

4. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्कों" पद से, प्रबंधकीय, तकनीकी अथवा परामर्शदात्री स्वरूप की सेवाओं के, जिनमें तकनीकी अथवा अन्य कार्मिकों की सेवाओं की व्यवस्था करना भी सम्मिलित है, प्रतिफल में अदायगियां करने वाले व्यक्ति के कर्मचारी को अदायगियां करने तथा अनुच्छेद 15 में वर्णित स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के लिए किसी व्यक्ति को की गयी अदायगियों से भिन्न किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की अदायगियां अभिप्रेत हैं।

5. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि तकनीकी सेवाओं के लिए रायल्टियों अथवा शुल्कों का लाभकारी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है और संविदाकारी राज्य में जिसमें तकनीकी सेवाओं के लिए रायल्टियां तथा शुल्क उद्भूत होते हैं, वहां पर स्थित स्थायी स्थापन के माध्यम से अथवा वहां पर स्थित स्थायी स्थापन से उस अन्य राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है जिससे अधिकार, संपत्ति अथवा संविदा के कारण तकनीकी सेवाओं के लिए रायल्टियां अथवा शुल्क अदा किए जाते हैं, ऐसे स्थायी स्थापन अथवा निश्चित आधार के साथ कारगर रूप से सम्बद्ध है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध, यथावस्था, लागू होंगे।

6. किसी संविदाकारी राज्य में तकनीकी सेवाओं के लिए रायल्टियां और शुल्क उद्भूत हुए माने जाएंगे, रायल्टियां और शुल्क अदा करने वाला स्वयं वह राज्य, कोई राजनीतिक उपमंडल, कोई सांविधिक निकाय, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का कोई निवासी हों। परन्तु, जहाँ तकनीकी सेवाओं के लिए रायल्टियां अथवा शुल्क अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, संविदाकारी राज्य में स्थायी स्थापन अथवा निश्चित आधार हो जिसके संबंध में अदायगियों करने का इकरारनामा किया गया हो और इस प्रकार की अदायगियां, ऐसे स्थायी स्थापन अथवा निश्चित आधार द्वारा वहन की जाती हों, तब तकनीकी सेवाओं के लिए रायल्टियां अथवा शुल्क उस राज्य में उद्भूत हुए माने जाएंगे जिसमें स्थायी स्थापन अथवा निश्चित आधार स्थित है।

7. जहाँ, रायल्टियां अथवा शुल्क अदा करने वाले और प्राप्तकर्ता के बीच अथवा उन दोनों तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण, तकनीकी सेवाओं के लिए अदा की गई रायल्टियों अथवा शुल्कों की रकम, उस रकम से किसी भी कारण से बढ़ जाती है जिसके लिए इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में यह रकम अदा की गयी होती, वहाँ इस अनुच्छेद के उद्देश्य केवल अन्तिम वर्णित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में अदायगियों के अतिरिक्त अंश पर इस अभिसमय के अन्य उद्देश्यों का अनुपालन करते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 14

पूंजीगत लाभ

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल संपत्ति के अंतरण से प्राप्त होने वाले अभिलाभ पर कर दूसरे राज्य में लगाया जा सकेगा।

2. किसी संविदाकारी राज्य के निवासी को शेयरों के अंतरण से अथवा अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त होने वाले अभिलाभों पर उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसमें वह कंपनी पंजीकृत है।

3. चलसंपत्ति के अंतरण से, जो उस स्थायी प्रतिष्ठान की व्यापारिक संपत्ति के अंग के रूप में जो एक संविदाकारी राज्य के उद्यम की दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित है, अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित चल संपत्ति के अंतरण से, जो एक संविदाकारी राज्य के निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ उलब्ध है, होने वाले लाभ पर, जिसमें ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान (अकेले अथवा संपूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निर्धारित स्थान के अंतरण से होने वाले लाभ भी शामिल हैं, उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

4. अंतर्राष्ट्रीय यातायात से चलाये जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों अथवा इस प्रकार के जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से संबंधित चल संपत्ति के अंतरण से प्राप्त लाभ केवल उन संविदाकारी राज्य में करावेय होंगे जिसमें उक्त उद्यम के कारगर-प्रबंध का स्थान स्थित है।

अनुच्छेद 15

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

1. एक संविदाकारी राज्य के कितने निवासी को, वृत्ति संबंधी सेवाओं अथवा इस प्रकार के अन्य स्वतंत्र कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय पर उस राज्य में कर लगा पड़ेगा। अन्य संविदाकारी राज्य में ऐसी आय पर कर लगाया जा सकेगा यदि ऐसी सेवाएं उस अन्य राज्य में की जाती हैं और यदि:—

(क) संगत वित्तीय वर्ष में कुल 90 दिन अथवा उन्ने अधिक की अवधि अथवा अवधियों के लिए वह उस अन्य राज्य में उत्स्थित रहा हो; अथवा

(ख) अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ उसे दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उलब्ध हो;

किन्तु प्रत्येक मामले में केवल उन्नी रकम पर ही कर लगाया जा सकेगा जो इन सेवाओं के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती हो।

2. "वृत्ति संबंधी सेवाएं" पद में, विशेष रूप से, वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षणिक अथवा शिक्षण संबंधी कार्यकलाप तथा चिकित्सकों, सर्जनों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुकारों, दंत-चिकित्सकों और लेखाकारों के स्वतंत्र कार्यकलाप भी शामिल हैं।

अनुच्छेद 16

पराश्रित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 17, 19, 20 और 21 के उद्देश्यों के अधीन रहते हुए, एक संविदाकारी राज्य के कितने निवासी को, नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतन, मजदूरी तथा अन्य इसी प्रकार के पारिश्रमिक पर कर केवल उन्ने राज्य में लगेगा, जब तक कि उसका नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में न हो। यदि नियोजन इस प्रकार होता है तो उन्ने उद्भूत ऐसे पारिश्रमिक पर कर उस दूसरे राज्य में लगाया जा सकता है।

2. पैराग्राफ 1 के उद्देश्यों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा, दूसरे संविदाकारी राज्य में किये गये नियोजन से उद्भूत पारिश्रमिक पर कर प्रथमो-लिखित राज्य में केवल उस स्थिति में लगाया जायेगा

(क) प्राप्तकर्ता संबद्ध कैलेंडर वर्ष में कितने उन्ने अवधि अथवा उन्ने अवधियों के लिए दूसरे राज्य में मौजूद रहा हो जो कुल मिलाकर 183 दिन से अधिक न हो, और

(ख) पारिश्रमिक की अदायगी ऐसे नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से की गयी हो, जो दूसरे राज्य का निवासी न हो, और

(ग) पारिश्रमिक व्यय का वहन किसी ऐसे स्थायी स्थापन अथवा किसी ऐसे निश्चित आधार द्वारा नहीं किया जाता है जो नियोजक का उस दूसरे राज्य में हो।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, अंतर्राष्ट्रीय यातायात में जलपोत पर अथवा वायुयान पर किये गये नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर कर उस संविदाकारी राज्य में लग सकेगा जिसमें उस उद्यम की प्रभावी प्रबंध व्यवस्था स्थित है।

अनुच्छेद 17

निदेशक-शुल्क

संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा किसी ऐसे कंपनी के निदेशक मण्डल अथवा उस कंपनी के ऐसे ह. किसी अन्य अंग के एक सदस्य का हैसियत से, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी हो, प्राप्त किए गए निदेशक-शुल्क तथा इसी प्रकार की अन्य अदायगियों पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा।

अनुच्छेद 18

कलाकार और खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 15 तथा 16 के उपबंधों के होते हुए भी, किसी थियेटर, चल-चित्र, रेडियो अथवा दूरदर्शन कलाकार अथवा संगीतकार जैसे किसी मनोरंजनकर्ता के रूप में अथवा एक खिलाड़ी के रूप में एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को उसके वैयक्तिक कार्यों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा जिस अन्य संविदाकारी राज्य में ऐसे कार्य किये गये हों।

2. जहां मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी द्वारा उसके वैयक्तिक क्रियाकलापों के संबंध में प्राप्त आय मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो अपितु अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, वहां अनुच्छेद 7, 15 तथा 16 के उपबंधों के होते हुए भी, उस आय पर कर उस संविदाकारी राज्य में लग सकेगा जिस राज्य में मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी द्वारा ऐसे क्रियाकलाप किये जाते हैं।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध लागू नहीं होंगे यदि उक्त मनोरंजनकर्ता अथवा उक्त खिलाड़ी की, संविदाकारी राज्य की यात्रा का व्यव, प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः दूसरे संविदाकारी राज्य की, जिसमें उस राज्य का राजनीतिक उप-मंडल, कोई सांविधिक निकाय अथवा स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल है, सरकारी तिधियों से पूर्णतः अथवा पर्याप्ततः किया गया हो।

1128 GI/84—2

अनुच्छेद 19

पेंशन और सामाजिक प्रतिभूति की अदायगियां

अनुच्छेद 20 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अधधीन किसी संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को विगत नियोजन के प्रतिफल के रूप में अदा की गई पेंशन और दूसरे इसी प्रकार के पारिश्रमिक पर तथा किसी ऐसी सार्वजनिक योजना के आगम दी गई पेंशनों और अन्य अदायगियों पर, जो सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का एक भाग हों, प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लग सकेगा।

अनुच्छेद 20

सरकारी सेवा

1. (क) एक संविदाकारी राज्य अथवा एक सांविधिक निकाय अथवा उसके स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यष्टि को, उस राज्य अथवा उस निकाय अथवा उसके प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में अदा किए गए, पेंशन से भिन्न पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा।

(ख) तथापि, ऐसे पारिश्रमिक पर केवल उस संविदाकारी राज्य में ही, जिसका उक्त व्यष्टि निवासी है, कर लग सकेगा, यदि सेवायें उसी राज्य में की गई हों और वह व्यष्टि :—

(1) उस राज्य का राष्ट्रिक है; अथवा

(2) सेवायें प्रदान करने के प्रयोजन मात्र के लिए उस राज्य का निवासी नहीं बना है।

2. (क) एक संविदाकारी राज्य अथवा एक सांविधिक निकाय अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यष्टि को, उस राज्य अथवा निकाय अथवा प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के लिए अदा की गई अथवा इन संस्थाओं द्वारा निमित्त तिधियों में से दी गई पेंशन पर उसी राज्य में कर लग सकेगा।

(ख) तथापि, ऐसी पेंशन पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा, जिसका कि वह व्यष्टि निवासी है, यदि वह उस राज्य का राष्ट्रिक है।

3. अनुच्छेद 16, 17 तथा 19 के उपबंध एक संविदाकारी राज्य अथवा सांविधिक निकाय अथवा उसके स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाये गये व्यापार के संबंध में की गई सेवाओं के बारे में प्राप्त पारिश्रमिक और पेंशनों पर लागू होंगे।

अनुच्छेद 21

विद्यार्थी और प्रशिक्षु

1. कोई विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक, तकनीकी, कृषि अथवा वन विद्या प्रशिक्षु, जो एक संविदाकारी राज्य का

दौरा करने के तुरन्त पूर्व दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है, अथवा था और जो, प्रथमोल्लिखित राज्य में केवल अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए उपस्थित है; अपने भरण पोषण शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के निमित्त अदायगियां प्राप्त करता है, उन पर उस राज्य में कर नहीं लगेगा बशर्ते कि ऐसी अदायगियां उस राज्य के बाहर के स्रोतों से उत्पन्न होती हों।

2. एक संविदाकारी राज्य में किसी विश्वविद्यालय अथवा अन्य संस्था में उच्च अध्ययन हेतु गए विद्यार्थी पर अथवा व्यावसायिक, तकनीकी, कृषि या वनविद्या प्रशिक्षु पर जो दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है, अथवा था तथा जो संबंधित कैलेंडर वर्ष में कुल 183 दिनों से अधिक की अवधि अथवा अवधियों के लिए उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उपस्थित है, उस राज्य में की गई सेवाओं के लिए प्राप्त पारिश्रमिक के संबंध में उस राज्य में कर नहीं लग सकेगा, बशर्ते कि की गई सेवाओं उसके अध्ययन अथवा प्रशिक्षण से संबंधित हों तथा उक्त पारिश्रमिक ऐसी कमाई हो जो उसके भरण-पोषण के लिए आवश्यक है। यदि वह संगत कैलेंडर वर्ष के दौरान कुल 183 दिनों अथवा उससे अधिक की अवधि अथवा अवधियों के लिए उस दूसरे राज्य में उपस्थित है, तो वह करों के संबंध में उन्हीं छूटों, राहतों अथवा छटीतियों का हकदार होगा, जो उस राज्य के अन्य निवासियों को अनमत्य होती है।

अनुच्छेद 22

अन्य आय

एक संविदाकारी राज्य के निवासी की आय की मदों पर, वे जहां कहीं भी उद्भूत होती हों, जिनका इस अभिसमय के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में विवेचन नहीं किया गया हो, केवल उस राज्य में कर लग सकेगा, सिवाय इसके कि यदि उस प्रकार की आय दूसरे संविदाकारी राज्य के स्रोतों से प्राप्त हुई है तो उस पर भी उस अन्य राज्य के कानून के अनुसार कर लग सकेगा।

अनुच्छेद 23

पूजी

1. अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ (2) में उल्लिखित अचल संपत्ति द्वारा निरूपित पूजी पर, जो एक संविदाकारी राज्य के निवासी के स्वामित्व में हो तथा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित हो, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. शेरों अथवा अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित अन्य निगमित अधिवारों द्वारा निरूपित तथा एक संविदाकारी राज्य के निवासी के स्वामित्वाधीन पूजी पर उस संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा, जिसमें उक्त कंपनी द्वारा धारित अचल संपत्ति स्थित है।

3. ऐसी चल संपत्ति द्वारा, जो किसी स्थायी स्थापन की व्यापारिक संपत्ति के अंग के रूप में एक संविदाकारी राज्य के उद्यम की तरह दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित है, अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल संपत्ति द्वारा, जो एक संविदाकारी राज्य के निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ उपलब्ध हैं, निरूपित पूजी पर उन दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

4. अंतर्राष्ट्रीय यातायात में चलाये जाने वाले जलयोतों और वायु यानों द्वारा और ऐसे जलयोतों और वायु यानों के संचालन से संबंधित चल संपत्ति द्वारा निरूपित पूजी पर कर केवल उस संविदाकारी राज्य में ही लगाया जा सकेगा जिसमें उक्त उद्यम के कारगर प्रबंध का स्थान स्थित है।

5. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की पूजी के सभी अंग, जिनका इस अनुच्छेद के पूर्वोक्त पैराग्राफों में विवेचन नहीं किया गया है, उभी राज्य में ही कराधेय होंगे, सिवाय इसके कि यदि इस प्रकार के अंग दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित हैं तो उन पर भी उस दूसरे राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद 24

दोहरे कराधान का अस्कारण

1. फिनलैण्ड में दोहरे कराधान का अस्कारण निम्न प्रकार से होगा :-

(क) जहां फिनलैण्ड का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है अथवा ऐसी पूजी का स्वामी है, जिस पर इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार भारत में कर लग सकता है वहां फिनलैण्ड उपायराफ (ख) के उपबंधों के अधीन,

(i) उस व्यक्ति की आय पर कर में से भारत में संवत्त आय पर कर के बराबर की रकम, कटौती के रूप में,

(ii) उस व्यक्ति की पूजी पर कर में से भारत में संवत्त पूजी पर कर के बराबर रकम कटौती के रूप में अनुशात करेगा।

तथापि, इस प्रकार की कटौती दोनों में से किसी भी स्थिति में, कटौती देने से पूर्व यथा-संगणित आय अथवा पूजी पर कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी, जो कि जैसा भी लागू हो, उस आय अथवा पूजी का प्रतीक है, जिग पर भारत में कर लग सकता है।

(ख) किसी ऐसी कंपनी द्वारा जो कि भारत की निवासी है, एक ऐसी कंपनी को, जो फिनलैण्ड की निवासी है, अदा दिये गये लाभांशों को फिनलैण्ड के कर से उस सीमा तक छूट होगी, जिस सीमा तक दोनों

कंपनियों के फिनलैण्ड की निवासी होने की स्थिति में फिनलैण्ड के कराधान कानूनों के अंतर्गत लाभार्थों का कर छूट प्राप्त होती है।

(ग) इस अभिसमय के किसी अन्य उपबंध के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जो भारत का निवासी है और उपर्युक्त अनुच्छेद 2 में उल्लिखित फिनलैण्ड कराधान कानूनों के अंतर्गत फिनलैण्ड का निवासी भी समझा जाता है, तो उस पर फिनलैण्ड में कर लग सकेगा। तथापि फिनलैण्ड आय पर अथवा पूँजी पर संदेन किसी भी भारतीय कर का फिनलैण्ड के कर में उप पैराग्राफ (क) के उपबंधों के अनुसार कटौती के रूप में अनुज्ञात करेगा। इस उप-पैराग्राफ के उपबंध केवल फिनलैण्ड के राष्ट्रिकों पर ही लागू होंगे।

(घ) जहाँ फिनलैण्ड के किसी निवासी द्वारा प्राप्त की गई आय अथवा उसके स्वामित्वाधीन पूँजी, अभिसमय के उपबंधों के अनुसार फिनलैण्ड में कर में मुक्त है, तो भी फिनलैण्ड ऐसे निवासी की शेष आय अथवा पूँजी पर कर की संगणना करते समय छूट-प्राप्त आय अथवा पूँजी को हिसाब में ले सकेगा।

2 पैराग्राफ 1 के प्रयोजनों के लिए, भारत में सदन करों में ऐसी कोई भी रकम शामिल समझी जाएगी जो कराधेय आय की संगणना में कटौती न दिए जाने अथवा निम्नलिखित धाराओं के अंतर्गत उस वर्ष के लिए कर में छूट अथवा घटौती न दिए जाने की स्थिति में भारतीय कर के रूप में सदेय होती है :

(क) आय-कर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 10(4), 10(4F), 10(6) (VIIक) 10(15) (iv), 32क, 33क, 33द, 35ग, 80जज, 80झ, और 80ड, जैसी वे इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख का लागू थी तथा उक्त तारीख से उनमें कोई परिवर्तन नहीं किये गये है, अथवा उनमें केवल ऐसे आंशिक परिवर्तन किए गए हैं जिनमें उनके सामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव न पड़ा हो; अथवा

(ख) कर से छूट अथवा घटौती, जिस पर दोनों संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों की सहमति हो मंजूर करने वाला कोई भी अन्य उपबंध जिसे बाद में अधिनियमित न किया जाए।

3 भारत में दोहरे कराधान का अपाकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा।

(क) भारत के किसी निवासी द्वारा ऐसी आय के संबंध में जिस पर भारत व फिनलैण्ड दोनों में कर लगाया गया है, फिनलैण्ड के कानूनों के अंतर्गत और इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार प्रत्यक्षतः अथवा

घटौती द्वारा देय फिनलैण्ड के वार की रकम को ऐसी आय के संबंध में भारत में देय कर के प्रति जमा मानने की अनुमति दी जाएगी, परन्तु वह रकम भारतीय कर के उस अनुपात से अधिक नहीं होगी, जो ऐसी आय तथा समस्त आय के बीच है, जिस पर भारतीय कर प्रभाय है।

(ख) उपर्युक्त उप पैराग्राफ (क) उल्लिखित जमा के प्रयोजनों के लिए, जहाँ भारत का निवासी एक ऐसी कंपनी है जिसके द्वारा अतिकर देय हो, वहाँ भारतीय कर के प्रति मंजूर की जाने वाली जमा की स्वीकृति प्रथमतः कंपनी द्वारा भारत में देय कर के प्रति दी जाएगी और शेष के संबंध में, यदि कोई हो उसके द्वारा भारत में देय अतिकर के प्रति दी जाएगी।

परन्तु जिस आय पर इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार कर नहीं लगाया जाता है उसे लगाये जाने वाले कर की दर की संगणना के लिए हिसाब में लिया जा सकता है।

अनुच्छेद 25

सम-व्यवहार

1 एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसे किसी कराधान अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी, जो उस कराधान से और उन संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर वैसे ही परिस्थितियों में लागू होती है, अथवा हो सकती है।

2 किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थायी स्थापन पर, उस दूसरे राज्य में ऐसा कराधान लागू नहीं किया जाएगा, जो उस दूसरे राज्य में वैसे ही कार्य में, उन्हीं परिस्थितियों में अथवा वैसे ही स्थितियों के अंतर्गत प्रबन्ध उद्यम पर लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हों। इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य को, एक स्थायी स्थापन के उन लाभों को प्राप्त न करने से रोका जाय, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम, पूर्वो-लिखित राज्य में कर की उस दर पर प्राप्त करता है, जो पूर्वो-लिखित संविदाकारी राज्य के एक वैसे ही उद्यम के लाभों पर लगाये गए कर की दरों की अपेक्षा अधिक हों और इसका अर्थ इस अभिसमय के अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ (3) के उपबंधों के प्रतिकूल भी नहीं लगाया जाएगा।

3 इस अनुच्छेद में निहित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि उससे एक संविदाकारी राज्य को, उस राज्य के अनिवासी व्यष्टियों को, कराधान के प्रयोजनों के लिए कोई ऐसी वैयक्तिक छूटें राहतें, तथा घटौतियाँ प्रदान करने के लिए बाध्य करता है, जो कानून द्वारा उस राज्य के निवासी व्यष्टियों को ही उपलब्ध है।

4. इस अनुच्छेद में निहित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह एक सविदाकारी राज्य को जहाजरानी के लाभों को उसी प्रकार संगणित करने के लिए बाध्य करती है, जैसा कि उस राज्य के उद्यमों के मामले में किया जाता है।

5. एक सविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूंजी पूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे सविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः, स्वामित्व अथवा नियंत्रण में है, प्रथमोक्त सविदाकारी राज्य में कोई सेवा कराधान अथवा तत्संबंधी कोई ऐसी अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी, जो उस कराधान और तत्सम्बन्धी अपेक्षाओं में भिन्न अथवा अधिक भागपूर्ण हों, जो उस प्रथमोक्त राज्य के अन्य वैसे ही उद्यमों पर लागू होती हैं, अथवा हो सकती हैं।

6. इस अनुच्छेद के उपबन्ध उन सभी करों पर लागू होंगे, जो इस अभिसमय में शामिल हैं।

अनुच्छेद 26

पारस्परिक करार कार्यविधि

1. जहाँ एक व्यक्ति यह समझता है कि एक अथवा दोनों सविदाकारी राज्यों के कार्यों के कारण उस पर कर लगा है, अथवा लगाया जाएगा, जो इस अभिसमय के उपबन्धों के अनुकूल नहीं है, तो वह उन राज्यों के राष्ट्रीय नियमों द्वारा उपबन्धित उपचारों के होते हुए भी अपना मामला उस सविदाकारी राज्य 1 के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रख सकता है जिसका वह निवासी है, अथवा यदि उसका मामला अनुच्छेद 25 के पैराग्राफ के अंतर्गत आता है, तो वह अपना मामला उस सविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका वह राष्ट्रिक है। यह मामला उस कार्य की प्रथम अधिसूचना के तीन वर्षों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसके कारण इस अभिसमय के उपबन्धों के अनुरूप कर नहीं लगा है।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी संशोधनक हल पर पहुँचने में असमर्थ हो तो, वह ऐसे कराधान के निवारण की दृष्टि से, जो इस अभिसमय के अनुरूप नहीं है, दूसरे सविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी की परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा।

3. इस अभिसमय की व्याख्या करने अथवा इसे लागू करने में यदि कोई कठिनाइयाँ अथवा शंकाएँ उत्पन्न हों, तो सविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे। विशिष्टतया, अनुच्छेद 10 में उल्लिखित मामलों में आय के आबंटन पर सहमति के प्रयोजनार्थ एक दूसरे से परामर्श कर सकते हैं। वे उन मामलों में दोहरे कराधान के अपाकरण के लिए परस्पर विचार-विमर्श कर सकते हैं, जिनकी व्यवस्था अभिसमय में नहीं की गई है।

4. सक्षम प्राधिकारियों में उपर्युक्त पैराग्राफ 2 और 3 में उल्लिखित कोई समझौता हो जाने की स्थिति में, इस प्रकार की आय पर कर लगाये जाएंगे तथा सविदाकारी राज्यों द्वारा ऐसे समझौते के अनुसार करों की वापसी अथवा जमा अनुज्ञात की जाएगी। इसे सविदाकारी राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों में किसी भी समय-समय के होते हुए भी कार्यान्वित किया जाएगा।

5. पूर्वोक्त पैराग्राफों में व्यक्त अभिप्राय को लेकर सहमति के प्रयोजनार्थ सविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी, एक दूसरे के साथ पत्र व्यवहार कर सकते हैं। सहमति के प्रयोजनार्थ जब विचारों का मौखिक आदान प्रदान उचित प्रतीत होता हो, तो ऐसे आदान-प्रदान किसी आयोग के माध्यम से किये जा सकते हैं, जिसमें सविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि हों।

अनुच्छेद 27

सूचना का आदान-प्रदान

1. सविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे, जो इस अभिसमय के अंतर्गत आने वाले करों से संबंधित, जहाँ तक उसके अंतर्गत कराधान उक्त अभिसमय के प्रतिकूल नहीं है, इस अभिसमय के अथवा सविदाकारी राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने अथवा जालसाजी या कर अपवंचन को रोकने के लिए आवश्यक है। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 द्वारा प्रतिबन्धित नहीं है। किसी सविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी, जिस प्रकार उस राज्य के राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना मानी जाती है और ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों को, (जिनमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय भी शामिल हैं) प्रकट किया जाएगा, जो उन करों के निर्धारण अथवा वसूली, उनके संबंध में प्रवर्तन अथवा अभियोजन अथवा उनसे संबंधित अपीलों के निर्धारण में अंतर्गस्त हों, जो इस अभिसमय के विषय हों। ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजनों के लिए करेंगे। वे इस सूचना को सार्वजनिक तौर पर न्यायालय कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे।

2. किसी भी स्थिति में, पैराग्राफ 1 के उपबन्धों का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा, जिसमें कि किसी सविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित भार डाला जाय:-

(क) एक अथवा दूसरे सविदाकारी राज्य की विधियों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना।

(ख) ऐसी सूचना देना जो एक अथवा दूसरे सविदाकारी राज्य की विधियों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्त नहीं हैं।

(ग) ऐसी सूचना देना, जिसमें कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसाय संबंधी गुप्त भेद अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सरकार की नीति (सरकारी आदेश) के प्रतिकूल हो।

अनुच्छेद 28

राजनयिक अधिकर्ता तथा कोंसली प्राधिकारी

अंतर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य नियमों के अन्तर्गत अथवा विशेष करारों के प्रावधानों के अंतर्गत, इस अभिसमय से, राजनैतिक अधिकर्ताओं अथवा कोंसली अधिकारियों के राज्यकर विषयक विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुच्छेद 29

प्रवर्तन

1. संविदाकारी राज्यों की सरकारें एक दूसरे को यह अधिसूचित करेंगी कि इस अभिसमय के प्रवर्तन के लिए संविधानिक अपेक्षाएं पूरी कर ली गई हैं।

2. यह अभिसमय, पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अधिसूचनाओं में से बाद वाली अधिसूचना के तीस दिनों के पश्चात लागू होगा और इसके उपबंध:-

(क) फिनलैंड में : () जिस कैलेंडर वर्ष में अभिसमय प्रवर्तित होता है, उसके परवर्ती वर्ष के जनवरी मास के प्रथम दिन अथवा उसके बाद प्राप्त की गई आय पर, स्रोत पर रोक लिए गए करों के संबंध में;

(ii) जिस कैलेंडर वर्ष में अभिसमय प्रवर्तित होता है, उसके परवर्ती वर्ष के जनवरी मास के प्रथम दिन अथवा उसके बाद प्रारम्भ हुई किसी भी कर-निर्धारणीय वर्ष के लिए प्रभार्य करों, आय पर अन्य करों और पूंजी पर करों के संबंध में;

(ख) भारत में : जिस कैलेंडर वर्ष में अभिसमय प्रवर्तित होता है, उसके परवर्ती वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिन अथवा उसके पश्चात प्रारम्भ हुए कर निर्धारण वर्षों के करों के संबंध में लागू होंगे।

3. आय के दोहरा करधान के परिहार के लिए फिनलैंड और भारत के मध्य हुआ करार, जिस पर 23 जून, 1961 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किये गये और जिसकी, टिप्पणियों के आदान-प्रदान द्वारा 16 अगस्त, 1979 को संशोधित किया गया था, उस समय से निष्प्र-

भावी हो जाएगा, जिस समय पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अनुसार इस अभिसमय के उपबंध लागू होंगे।

अनुच्छेद 30

समाप्ति

यह अभिसमय उस समय तक लागू रहेगा, जब तक कि संविदाकारी राज्यों में से एक राज्य द्वारा इसे समाप्त नहीं कर दिया जाता। संविदाकारी राज्यों में से कोई भी राज्य अभिसमय के लागू होने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के पश्चात पड़ने वाले किसी भी कैलेंडर वर्ष की समाप्ति से कम से कम छः माह पहले राजनयिक माध्यम से समाप्ति का नोटिस देकर अभिसमय को समाप्त कर सकेगा ऐसी स्थिति में यह अभिसमय;

(क) फिनलैंड में:

(i) जिस कैलेंडर वर्ष में नोटिस दिया गया हो, उसके अगले परवर्ती कैलेंडर वर्ष में, 1 जनवरी को अथवा उसके पश्चात प्राप्त की गई आय पर स्रोत पर रोक लिए गए करों के संबंध में;

(ii) जिस कैलेंडर वर्ष में नोटिस दिया गया हो, उसके अगले परवर्ती कैलेंडर वर्ष में, 1 जनवरी को अथवा उसके पश्चात प्रारम्भ होने वाले किसी भी कर निर्धारण वर्ष लिए प्रभार्य करों में आय पर अन्य करों और पूंजी पर करों के संबंध में;

(ख) भारत में, जिस कैलेंडर वर्ष में नोटिस दिया गया हो उसके परवर्ती दूसरे कैलेंडर वर्ष में 1 अप्रैल को अथवा उसके पश्चात प्रारम्भ होने वाले किसी भी कर-निर्धारण वर्ष के लिए करों के संबंध में;

निष्प्रभावी हो जाएगा।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किये हैं। हेलसिंकी में 10 जून, 1983 को हिन्दी, फिनिश और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतिग्रंथों में, किए गए, सभी पाठ सामानतः प्रामाणिक होंगे सिवाय इसके कि अर्थ निरूपण की भिन्नता के मामले में अंग्रेजी पाठ अप्रभावी होगा।

एम० रसगोत्रा,

भारत सरकार की ओर से

मस्ती दुआबिनैन,

फिनलैंड सरकार की ओर से

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Foreign Tax Division)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 20th November, 1984

INCOME-TAX

G.S.R. 786(E).—Whereas the annexed Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Finland for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital has come into force on the notification by both the Contracting States to each other of the compliance of the constitutional requirements, as required by Paragraph 1 of Article 29 of the said Convention;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), section 24A of the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964) and section 44A of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Convention shall be given effect to in the Union of India.

ANNEXURE

CONVENTION

BETWEEN THE REPUBLIC OF INDIA

AND

THE REPUBLIC OF FINLAND

FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND
ON CAPITAL

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Finland,

Desiring to conclude a new Convention for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital,

Have agreed as follows :

Article 1

PERSONAL SCOPE

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

TAXES COVERED

1. The taxes which are the subject of the present Convention are :

(a) in Finland :

- (i) the state income and capital tax;
- (ii) the communal tax;
- (iii) the church tax;
- (iv) the sailors' tax; and
- (v) the tax withheld at source from non-residents' income; (hereinafter referred to as "Finnish tax");

(b) in India :

- (i) the income-tax including any surcharge thereon;
 - (ii) the sur-tax; and
 - (iii) the wealth tax;
- (hereinafter referred to as "Indian tax").

2. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of significant changes which have been made in their respective taxation laws.

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires :

- (a) the term "person" includes an individual a company and any other body of persons;
- (b) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;
- (c) the term "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- (d) the term "national" means any individual possessing the nationality of a Contracting State, and any legal person, partnership and association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State;
- (e) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

(f) the term "competent authority" means :

- (i) in Finland, the Ministry of Finance or its authorised representative;
- (ii) in India, the Ministry of Finance (Deptt. of Revenue).

2. As regards the application of the Convention by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that State concerning the taxes to which the Convention applies.

Article 4

FISCAL DOMICILE

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States then his status shall be determined as follows.

- (a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
- (b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;
- (c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;
- (d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially :

- (a) a place of management;
- (b) a branch;
- (c) an office;
- (d) a factory;
- (e) a workshop;
- (f) a mine, a quarry or any other place of extraction of natural resources;
- (g) warehouse; and
- (h) premises used as a sales outlet or for receiving or soliciting orders.

3. The term "permanent establishment" also includes :

- (a) a building site, a construction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith, but only where such site, project or activities continue for a period of more than six months;
- (b) a building site, a construction, assembly or installation project or supervisory activity being incidental to the sale of machinery or equipment, where such site, project or activity continues for a period not exceeding six months and the charges payable for the project or supervisory activity exceed 10 per cent of the sale price of the machinery or equipment.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include :

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information or for scientific research, being activities solely of a preparatory or auxiliary character in the business of the enterprise.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person—other than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies—is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State that enterprise

shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, if such a person :

- (a) has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph; or
- (b) has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise.

6. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, an insurance enterprise of a Contracting State shall, except in regard to re-insurance, be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it collects premiums in the territory of that other State or insures risks situated therein through a person other than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies.

7. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he shall not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

8. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company or a permanent establishment of the other.

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. (a) The term "immovable property" shall, subject to the provisions of sub-paragraphs (b) and (c) have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated.

(b) The term "immovable property" shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and

forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources.

(c) Ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. Where the ownership of shares or other corporate rights in a company entitles the owner of such shares or corporate rights to the enjoyment of immovable property held by the company, the income from the direct use, letting, or use in any other form of such right of enjoyment may be taxed in the Contracting State in which the immovable property is situated.

5. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to (a) that permanent establishment; (b) sales in that other State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that permanent establishment; or (c) other business activities carried on in that other State of the same or similar kind as those effected through that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses, so incurred, whether

in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, which are allowed under the provisions of the domestic law of the Contracting State in which the permanent establishment is situated. However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission, for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on money lent to the permanent establishment. Likewise no account shall be taken, in determining the profits of a permanent establishment, for amounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses), by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on money lent to the head office of the enterprise or any of its other offices.

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary. The method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

AIR TRANSPORT

1. Income derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

2. Paragraph 1 shall likewise apply in respect of participations in pools of any kind by enterprises engaged in air transport.

3. For the purposes of this Article :

- (a) interest on funds connected with the operation of aircraft in international traffic shall be regarded as income from the operation of such aircraft; and
- (b) the term "operation of aircraft" shall include transportation by air of persons, livestock, goods or mail, carried on by the owners or lessees or charterers of aircraft, including the sale of tickets for such transportation on behalf of other enterprises, the incidental lease of aircraft on a charter basis and any other activity directly connected with such transportation.

Article 9

SHIPPING

1. Income of an enterprise of a Contracting State derived from the other Contracting State from the operation of ships in international traffic may be taxed in that other State, but the tax chargeable in that other State on such income shall be reduced by an amount equal to fifty per cent of such tax.

2. Paragraph 1 shall not apply to profits arising as a result of coastal traffic.

Article 10

ASSOCIATED ENTERPRISES

Where

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State ;

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article 11

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying

the dividends is a resident and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed :

- (a) 15 per cent of the gross amount of the dividends if the recipient is a company (other than a partnership) which holds directly at least 10 per cent of the capital of the company paying the dividends ;
- (b) 25 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The provisions of sub-paragraph (a) of paragraph 2 would apply in respect of dividends arising out of investments made after the date of signature of this Convention.

4. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

6. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other state may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 12

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State, provided, however, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the interest.

2. The provisions of paragraph 1 would apply in respect of interest payable arising out of investments made after the date of signature of this Convention.

3. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtors profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds and debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

4. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the recipient of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

5. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that state itself, a political subdivision, a statutory body, a local authority or, a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13

ROYALTIES AND FEES FOR TECHNICAL SERVICES

1. Royalties and fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties and fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State; provided that where the royalties or fees for technical services are paid to a resident of the other Contracting State who is the beneficial owner thereof and they are paid in respect of a right or property which is first granted, or under a contract which is signed, after the date of signature of this Convention, the tax so charged shall not exceed 30 per cent of the gross amount of the royalties and fees for technical services.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind including rentals received as a consideration for the use of, or the right to use :

- (a) any patent, trademark, design or model, plan, secret formula or process ;
- (b) industrial commercial, or scientific equipment or information concerning industrial, commercial or scientific experience ;
- (c) any copyright of literary, artistic or scientific work, cinematograph films or tapes for radio or television broadcasting ;

but does not include royalties or other amounts paid in respect of the operation of mines or quarries or of the extraction or removal of natural resources.

4. The term "fees for technical services" as used in this Article means payments of any kind to any person, other than payments to an employee of the person making the payments and to any individuals for independent personal services mentioned in Article 15, in consideration for services of a managerial, technical or consultancy nature, including the provision of services of technical or other personnel.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for technical services arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right, property or contract in respect of which the royalties or fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

6. Royalties and fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a statutory body, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the obligation to make the payments was incurred, and such payments are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the royalties or fees for technical services exceeds, for whatever reason, the amount which would have been paid in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 14

CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in paragraph 2 of Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares or other corporate rights may be taxed in the Contracting State in which the company is registered.

3. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

4. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

Article 15

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character may be taxed in that State. Such income may also be taxed in the other Contracting State if such services are performed in that other State and if :

- (a) he is present in that other State for a period or periods aggregating 90 days or more in the relevant fiscal year ; or
- (b) he has a fixed base regularly available to him in that other State for the purpose of performing his activities ;

but in each case only so much of the income as is attributable to those services.

2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 16

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 17, 19, 20 and 21, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State

unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if :

- (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the calendar year concerned, and
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
- (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

Article 17

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or any other similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 18

ARTISTES AND ATHLETES

1. Notwithstanding the provisions of Articles 15 and 16, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 15 and 16, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the visit to a Contracting State of the entertainer or the athlete is directly or indirectly supported, wholly or substantially, from the public funds of the other Contracting State, including a political subdivision, of a statutory body or a local authority of that other State.

Article 19

PENSIONS AND SOCIAL SECURITY PAYMENTS

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 20 pensions and other similar remuneration in consideration of past employment paid by a resident of, and pensions and other payments made under a public scheme which is part of the social security system of, a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State.

Article 20

GOVERNMENT SERVICE

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a Statutory body or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or body or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the Contracting State of which the individual is a resident if the services are rendered in that State and the individual :

- (i) is a national of that State; or
- (i) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. (a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a statutory body or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or body or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such pension shall be taxable only in the Contracting State of which the individual is a resident if he is a national of that State.

3. The provisions of Article 16, 17 and 19 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a statutory body or a local authority thereof.

Article 21

STUDENTS AND APPRENTICES

1. Payments which a student or business, technical, agricultural or forestry apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned state solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

2. A student at a university or other institution for higher education in a Contracting State, or a business, technical, agricultural or forestry apprentice who is or was immediately before visiting the other Contracting State a resident of the first-mentioned State and who

is present in the other Contracting State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the calendar year concerned, shall not be taxed in that other State in respect of remuneration for services rendered in that State, provided that the services are in connection with his studies or training and the remuneration constitutes earnings necessary for his maintenance. If he is present in that other State for a period or periods aggregating 183 days or more in the calendar year concerned, he shall be entitled to the same exemptions, reliefs or reductions in respect of taxes as are granted to residents of that State.

Article 22

OTHER INCOME

Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State except that, if such income is derived from sources in the other Contracting State it may also be taxed in accordance with the law of that other State.

Article 23

CAPITAL

1. Capital represented by immovable property referred to in paragraph 2 of Article 6, owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Capital represented by shares or other corporate rights referred to in paragraph 4 of Article 6 and owned by a resident of a Contracting State may be taxed in the Contracting State in which the immovable property held by the company is situated.

3. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or by movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, may be taxed in that other State.

4. Capital represented by ships and aircraft operated in international traffic, and by movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

5. Elements of capital of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing paragraphs of this Article shall be taxable only in that State except that, if such elements are situated in the other Contracting State they may also be taxed in accordance with the law of that other State.

Article 24

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. In Finland double taxation shall be eliminated as follows :

- (a) Where a resident of Finland derives income or owns capital which, in accordance with

the provisions of this Convention, may be taxed in India, Finland shall, subject to the provisions of sub-paragraph (b), allow :

- (i) as a deduction from the tax on income of that person, an amount equal to the tax on income paid in India,
- (ii) as a deduction from the tax on capital of that person, an amount equal to the tax on capital paid in India.

Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the tax on income or on capital, as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the income or the capital which may be taxed in India.

- (b) Dividends paid by a company which is a resident of India to a company which is a resident of Finland shall be exempt from Finnish tax to the extent that the dividends would have been exempt from tax under Finnish taxation law if both companies had been residents of Finland.

- (c) Notwithstanding any other provision of this Convention, an individual who is a resident of India and under Finnish taxation law with respect to the Finnish taxes referred to in Article 2 also is regarded as a resident of Finland may be taxed in Finland. However, Finland shall allow any Indian tax paid on the income or the capital as a deduction from Finnish tax in accordance with the provisions of sub-paragraph (a). The provisions of this sub-paragraph shall apply only to nationals of Finland.

- (d) Where in accordance with any provisions of the Convention income derived or capital owned by a resident of Finland is exempt from tax in Finland, Finland may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income or capital of such resident, take into account the exempted income or capital.

2. For the purposes of paragraph 1, taxes paid in India shall be deemed to include any amount which would have been payable as Indian tax but for a deduction allowed in computing the taxable income or an exemption or reduction of tax granted for that year under :

- (a) sections 10(4), 10(4A), 10(6)(vii), 10(15)(iv), 32A, 33A, 35B, 35C, 80HH, 80I, 80J and 80K of the Income-tax Act, 1961 (No. 43 of 1961), so far as they were in force on and have not been modified since the date of signature of this Convention, or have been modified only in minor respects so as not to affect their general character; or
- (b) any other provision which may subsequently be enacted granting an exemption or reduction from tax which is agreed by the competent authorities of the two Contracting States.

3. In India double taxation shall be eliminated as follows :

- (a) The amount of Finnish tax payable, under the laws of Finland and in accordance with the provisions of this Convention, whether directly or by deduction, by a resident of India, in respect of income which has been subjected to tax both in India and Finland shall be allowed as a credit against the Indian tax payable in respect of such income but in an amount not exceeding that proportion of Indian tax which such income bears to the entire income chargeable to Indian tax.
- (b) For the purposes of the credit referred to in sub-paragraph (a) above, where the resident of India is a company by which surtax is payable, the credit to be allowed against the Indian tax shall be allowed in the first instance against the income-tax payable by the company in India and, as to the balance, if any, against the surtax payable by it in India.

Provided that income which in accordance with the provisions of this Convention is not to be subjected to tax may be taken into account in calculating the rate of tax to be imposed.

Article 25

NON-DISCRIMINATION

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities in the same circumstances or under the same conditions. This provision shall not be construed as preventing a Contracting State from charging the profits of a permanent establishment which an enterprise of the other Contracting State has in the first-mentioned State at a rate of tax which is higher than that imposed on the profits of a similar enterprise of the first-mentioned Contracting State, nor as being in conflict with the provisions of paragraph 3 of Article 7.

3. Nothing contained in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to individuals not resident in that State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes which are by law available only to individuals who are so resident.

4. Nothing contained in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to compute the shipping profits in the same manner as is done in the case of enterprises of that State.

5. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

6. The provisions of this Article shall apply to all taxes which are covered by this Convention.

Article 26

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 25, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. In particular, they may consult together for the purpose of reaching an agreement on the allocation of income in cases referred to in Article 10. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. In the event the competent authorities reach an agreement referred to in paragraphs 2 and 3, taxes shall be imposed on such income, and refund or credit of taxes shall be allowed by the Contracting States in accordance with such agreement. It shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

5. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 27

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents) as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention or for the prevention of fraud or evasion of taxes. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies involved in the assessment or collection of, the enforcement of prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation :

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or the administrative practice of that or of the other Contracting States ;
- (b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting States ;
- (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (order, public).

Article 28

DIPLOMATIC AGENTS AND CONSULAR OFFICERS

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 29

ENTRY INTO FORCE

1. The Governments of the Contracting States shall notify each other that the constitutional requirements for the entry into force of this Convention have been complied with.

2. The Convention shall enter into force thirty days after the date of the later of the notifications referred to in paragraph 1 and its provisions shall have effect :

(a) in Finland :

- (i) in respect of taxes withheld at source, to income derived on or after 1 January in

the calendar year next following the year in which the Convention enters into force;

- (ii) in respect of other taxes on income, and taxes on capital, to taxes chargeable for any taxable year beginning on or after 1 January, in the calendar year next following the year in which the Convention enters into force;

- (b) in India, in respect of taxes for assessment years beginning on or after 1 April of the calendar year next following the year in which the convention enters into force.

3. The Agreement between Finland and India for the avoidance of double taxation of income, signed at New Delhi on 23 June 1961, as amended by exchange of notes on 16 August 1979, shall cease to have effect at the time that the provisions of this Convention shall be effective in accordance with the provisions of paragraph 2.

Article 30

TERMINATION

This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year following after the period of five years from the date on which the Convention enters into force. In such event, the Convention shall cease to have effect :

(a) in Finland :

- (i) in respect of taxes withheld at source, to income derived on or after 1 January in the calendar year next following the year in which the notice is given;

- (ii) in respect of other taxes on income, and taxes on capital, to taxes chargeable for any taxable year beginning on or after 1 January in the calendar year next following the year in which the notice is given;

- (b) in India, in respect of taxes for any assessment year beginning on or after 1 April of the second calendar year following that in which the notice is given.

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done in duplicate at Helsinki on this 10th day of June 1983, in the Hindi, Finnish and English languages, all the texts being equally authentic except that in the case of divergence of interpretation the English text shall prevail.

Sd/-

(M. RASGOTRA)

For the Government
of the Republic of India :

Sd/-

(MATTI TUOVINEN)

For the Government
of the Republic of Finland :

सा० का० नि० 787 (अ) —केन्द्रीय सरकार, धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 44क के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, फिनलैंड को व्यक्तिकारी देश घोषित करती है।

[फा० सं० 501/13/80-एफ. टी. डी.]

सी० के० तिक्कु, संयुक्त सचिव

G.S.R. 787(E).—In exercise of the powers conferred by the Explanation to section 44A of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Government hereby declares Finland to be a reciprocating country.

[F. No. 501/13/80-FTD]

C. K. TIKKU, Jt. Secy.